(b) to (d) I.T.D.C.'s Annual Plan 1998-99 docs not include any proposal for the construction of a Hotel in the Vizag area. Accommodation for the convenience of middle class tourists are available in and around the area.

सेना में अधिकारियों के रिक्त पद

*46 **श्री डी.पी. यादव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेना में अधिकारियों के कुल कितने पद इस समय रिक्त हैं,

(ख) क्या यह सच है कि सेना में अधिकारियों की कमी से सेना का मनोबल गिरा है, और

(ग) क्या सरकार ने अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने हेतु कोई कार्रवाई की है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नांडिस) : (क) से (ग) इस समय सेना में 13,271 अफसरों की कमी है। तथापि, अफसरों की कमी होना नई बात नहीं है। विगत में भी यह कमी अलग-अलग स्तरों पर नहीं है। अफसरों की कमी से सेना के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

सेना में अफसर संवर्ग में कमी पूरी किए जाने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए गए हैं, यथा विश्वविद्यालय प्रवेश योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर के "ग" प्रमाण-पत्र धारकों को अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अफसर के रूप में भर्ती किए जाने के लिए उन्हें सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा में बैठने से छूट देना महिलाओं की अफसरों के रूप में भर्ती, सेवारत जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों को विशेष कमीशन प्राप्त अफसर संवर्ग में पदोन्नति देना और 10+2 तकनीकी प्रवेश योजना शुरू करना।

एक व्यावसायिक विज्ञापन एजेंसी की सहायता से 1997-98 के दौरान सेना की छवि-प्रदर्शन का अभियान चलाया गया था। इस दिशा में हुई उपलब्धियों को और समेकित करने के लिए सरकार ने इस अभियान का चरण – II शुरू करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों में और सुधार करते हुए उन्हें लागू कर दिया है।

यह आशा है कि इन सभी प्रयायों में समवेत प्रभाव के फलस्वरूप भर्ती में वृद्धि होगी, जिससे निकट भविष्य में अफसरों की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी।

Action Plan to fight insurgency in North-East

*47. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have since prepared an Action Plan to fight increasing insurgency in North-East region;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) Insurgency in trite North East has never been looked upon only as a law and order problem. The development and deepening of democratic processes has been the basic framework within which the problems of the North-East have been approached. Development strategy since Independence has been pursued within the broad framework of planning with a view to ensure that people develop along the lines of their own genius and nothing should be imposed on them and that traditional way of life and culture are encouraged. The efforts should be to train and build indigenous teams to do the work of administration and development and that development should come through indigenous social and cultural institutions.

The strategy to curb insurgency includes a willingness to meet and discuss legitimate grievances; resolve that violence would not be tolerated; friendly relations with neighbouring countries; accelerated infrastructural development; stress on employment schemes; and good governance and decentralisation.

The State Governments have formulated their own Action Plans to fight insurgency. The Union Government monitors, cordinates and reinforces these Plans. The steps taken by the Central